DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 6 अगस्त 2022 ED--------------------

रामलीलाओं को राहत, सिक्योरिटी चार्ज अब 15 रुपये/ वर्ग मीटर ही

खाना बनाने के लिए ईटीपी भी लगाने की जरूरत नहीं

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

रामलीला कमिटियों के प्रतिनिधियों की बीजेपी नेताओं के साथ LG से मुलाकात

डीडीए पार्कों में रामलीला आयोजन के लिए अब रामलीला कमिटियों को भारी-भरकम सिक्योरिटी चार्ज देने की जरूरत नहीं। शुक्रवार को उपराज्यपाल वी.के. ने पार्कों के बुकिंग के लिए जो सिक्योरिटी चार्ज 66 रुपये/ वर्ग मीटर तय किया था, उसे घटा कर 15 रुपये/ वर्ग मीटर करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पार्कों में खाना बनाने या स्टॉल लगाने के लिए ईटीपी लगाने का प्रावधान भी खत्म कर दिया है।

रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा व वेस्ट दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को रामलीला आयोजन में होने वाली दिक्कतों को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की और समस्याएं बताईं। उनकी समस्याएं सुनने के बाद राज्यपाल ने रामलीला ग्राउंड में ईटीपी लगाने को जो शर्तें डीडीए ने तय की थीं, उसे खत्म कर दिया। सिक्योरिटी चार्ज के रूप में जो अग्रिम 66 रुपये/ वर्ग मीटर जमा कराने का प्रावधान बनाया है, उसे कम कर 15 रुपये/ वर्ग मीटर कर दिया। सफाई शुल्क को कम कर 2.75 रुपये/ वर्ग मीटर कर दिया है। रामलीला कमिटियों को एक मुश्त जो 5 लाख रुपये जमा कराना था, उसमें भी उपराज्यपाल ने राहत दी है। ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के प्रधान सुरेश बिंदल ने उपराज्यपाल के इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि असली समस्या डीडीए ग्राउंड की बुकिंग को लेकर ही थी। पूर्वी दिल्ली में जितने भी स्थानों पर बड़े स्तर पर रामलीलाओं का आयोजन होता है, वह डीडीए पार्क में ही होता है। श्री रामलीला कमिटी (जनकपुरी) के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार चावला का कहना है कि डीडीए ने जो नई शर्तें तय की थीं, उसे लेकर उन्होंने काफी पहले इसकी शिकायत एलजी से की थी।

सभी बंदिशों को खत्म करने का दिया गया आदेश

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, AUGUST 6, 2022
NAME OF NEWSPAPERS-----------------------------------DATED-----------------

Another Bid To Shed The Legacy, Cut Waste By A Third At Landfills

MCD Invites Tenders For Disposal Of 90L Tonnes Garbage Via Bioremediation, Biomining

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The Municipal Corporation of Delhi has finally invited tenders for the disposal of 90 lakh tonnes of legacy waste in the city's three overused landfills through bioremediation and biomining in 18 months. This could help the civic body get rid of at least a third of the 280 lakh tonnes of legacy waste lying at the Ghazipur, Bhalswa and Okhla landfills.

Till date, MCD has claimed to have processed only 55 tonnes of legacy waste with the help of 85 trommel machines. But disposing of the output generated after biomining, including inert and refuse-derived fuel, has always been a burden.

"Several concessionaires are engaged for biomining and transporting of inert in addition to supplying the material to agencies like the National Highway Authority of India," said an official. "We still have a major portion of the inert accumulating at the landfills every day. By taking up this space, other day-to-day operations at the already saturated landfills are being affected."

The move to engage major disposal companies has come in the wake of targets given in the report submitted in June to lieutenant governor V K Saxena on flattening the landfills. For Ghazipur, the deadline is March 2024, for Bhalswa December 2023 and for Okhla, September 2023.

MCD expects it won't have to spend more than Rs 250 crore at one landfill for the biomining and disposal processes. "Different concessionaires will be designated for each landfill. Depending on the outcome, we may increase the quantity or intensify the process to continue reducing the accumulated waste," said an official.

While the request for proposal was invited on August 3, MCD aims to finalise the technical bid within September 3, followed by finalisation of the financial bid.

Earlier, there was a plan to dispose of 30 lakh tonnes of waste at Ghazipur, but the cost was proving prohibitive.

Defining the three landfills in the city as a national shame and also presenting grave health hazards, lieutenant governor V K Saxena asked the general public on July 1 to come out with ideas that could help in reducing these unseemly mountains of garbage.

"The stinking heaps over 50 metre high in the capital are not only grave health hazards but a national shame! Your suggestions and participation will be of value in the efforts to get rid Delhi of over 28 million metric tonnes of waste," the LG had tweeted.

As of now, 5,300 tonnes of fresh waste go to the waste-to-energy plants and a small portion to the composting plants. "The remaining unprocessed municipal solid waste (around 5,000 tonnes) goes to the landfills at Ghazipur, Okhla, and Bawana," claimed civic officials.

To ensure no fresh and unsegregated municipal waste is dumped at three landfills every day in the future, MCD has targeted the establishment of two more waste-to-energy plants by 2024-25, taking the total number of such plants to five and their total processing capacity to 11,000 tonnes per day.

CITY'S LANDFILLS OF WOES

Total waste at three landfills	GHAZIPUR	BHALSWA	OKHLA
280 lakh tonnes	140 lakh tonnes	80 lakh tonnes	60 lakh tonnes

Waste processed so far | 55 lakh metric tonnes

NUMBER OF TROMMEL MACHINES

Trommel machine

Bhalswa	Okhla	Ghazipur
52 (process 300 tonnes of waste per day)	25 (8 new ones planned)	8 big trommel machines (process around 500 TPD)

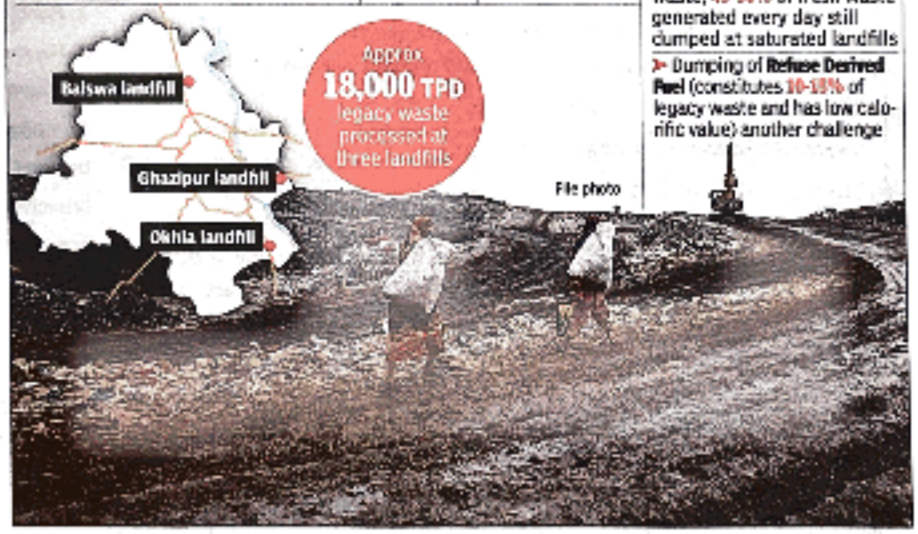

CHALLENGES

- MCD racing against time to flatten the three landfills by **March 2024**
- Non-availability of space to dump inert a major issue
- Inert constitutes 60% of total legacy waste and agencies like NHAI can take a maximum of **10 lakh tonnes** in a year for road construction projects
- MCD has asked DDA to provide more space for dumping inert
- No alternative land available for dumping fresh waste; 45-50% of fresh waste generated every day still dumped at saturated landfills
- Dumping of **Refuse Derived Fuel** (constitutes 10-15% of legacy waste and has low calorific value) another challenge

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF --------DATED----

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2022 दैनिक जागरण 7

एलजी ने दूर की लीला मंचन में आने वाली परेशानी : गुप्ता

- आनलाइन मिलेगी अनुमति, आयोजन स्थल का किराया भी कम
- प्रवेश वर्मा ने कहा, अब रात 12 बजे तक लोग देख सकेंगे रामलीला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना ने राजधानी में रामलीला समितियों की परेशानी दूर कर दी है। उन्हें अब आयोजन की अनुमति के लिए एक से दूसरे विभाग में नहीं भटकना होगा। आयोजन की अनुमति आनलाइन मिलेगी। आयोजन स्थल का किराया भी कम कर दिया गया है।

प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि शुक्रवार को आरएसएस के दिल्ली प्रांत संघ चालक कुलभूषण आहूजा, पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा व दिल्ली धार्मिक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ राजनिवास में एलजी से मुलाकात कर उन्हें रामलीला आयोजन में होने वाली परेशानी की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ ही डीडीए, नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। एलजी ने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए मौके पर ही निर्णय लिए हैं।

उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल का किराया दस रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया था। उसे अब कम करके 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। आयोजकों को अब संबंधित विभाग के पास दस लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा नहीं करनी होगी। आयोजन स्थल पर अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने की शर्त वापस ले ली गई है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम जनता के सहयोग से धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस तरह के आयोजन से युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। एलजी के फैसले से रामलीला मंचन के साथ अन्य आयोजन में आसानी होगी। लीला मंचन का समय बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया गया है।

9
दैनिक जागरण
नई दिल्ली,
8 अगस्त, 2022

आवश्यक कदम

दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 का ड्राफ्ट बदलकर और व्यावहारिक बनाया जाएगा, जो सर्वथा उचित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसके कुछ प्रावधानों की समीक्षा करना चाहते हैं। एलजी का मानना है कि पिछले कुछ दशक में दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनियोजित विकास हुआ है और गंदगी भी बढ़ी है। यहां अनधिकृत कालोनियां बसती चली गईं और झुग्गियों की बाढ़ आ गई है। एलजी ऐसी व्यावहारिक नीतियां चाहते हैं, जिनसे दिल्ली को स्वच्छ बनाने के साथ ही राजधानी का नियोजित विकास किया जा सके और झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सके।

> मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट में समस्याओं के समाधान के साथ ही नियोजित विकास को सुनिश्चित करें

दिल्ली के अनियोजित विकास के लिए अब तक बने मास्टर प्लानों को जिम्मेदार ठहराया जाना कतई गलत नहीं है। मास्टर प्लान में दिल्ली के नियोजित विकास को लेकर व्यावहारिक प्रविधान नहीं किए जाने की वजह से ही इसे एक नियोजित वैश्विक महानगर बनाने में सफलता नहीं मिल सकी। दिल्ली में अनियोजित विकास होता गया और झुग्गियां बसती गईं, साथ ही सीवरेज इत्यादि की भी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। यही वजह है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने में दिल्ली में व्यवस्थित सीवरेज सिस्टम न होना एक बड़ी बाधा बना हुआ है। वायु प्रदूषण भी वर्ष भर दिल्लीवासियों की सांसें फुलाता रहता है। निश्चित तौर पर वर्ष 2041 के लिए जो मास्टर प्लान बने, वह इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद बनना चाहिए। साथ ही इसे व्यावहारिक भी होना चाहिए, ताकि उसकी योजनाओं पर अमल कर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

हिन्दुस्तान
शनिवार
6 अगस्त 2022, नई दिल्ली

राजधानी में आसान होगा रामलीला का आयोजन

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में रामलीला का आयोजन आसान होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रामलीला आयोजन को लेकर अनुमति प्रक्रिया को आसान करने के निर्देश दिए हैं। रामलीला महासंघ पदाधिकारियों व भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को उपराज्यपाल से मुलाकात की।

उपराज्यपाल ने ट्वीट कर परेशानी दूर करने के निर्देश दिए: उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट संदेश में भी इस मुलाकात की फोटो साझा की। मुलाकात के दौरान रामलीला समितियों की ओर से भी आयोजन में आने वाली परेशानियों को रखा गया। इस पर उपराज्यपाल ने सभी संबंधित संस्थाओं को रामलीला के आयोजन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि देने की प्रक्रिया भी आसान करने को कहा।

सभी समस्याओं का समाधान

श्रीधार्मिक लीला कमेटी के महासचिव धीरज धर गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की रामलीलाओं की जो भी समस्याएं थी, उप राज्यपाल ने उन सभी का समाधान कर दिया है। डीडीए द्वारा लगाया गया शुल्क भी माफ कर दिया गया है। संयंत्र लगाने में होने वाला तीस-पैंतीस लाख रुपये का खर्चा भी अब करने की जरूरत नहीं रहेगी। बारह बजे तक की अनुमति भी दे दी गई है। रामलीलाओं में अब बाजार भी लगेंगे और झूले भी लगाए जा सकेंगे।

बैठक में कई रियायत देने की बात : रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के मुताबिक, लगभग पचास मिनट तक यह मुलाकात चली। उपराज्यपाल के आदेश पर इसमें डीडीए, निगम, पीडब्ल्यूडी व दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। महासंघ की समस्याएं सुनने के बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली में होने वाली 650 से अधिक रामलीला कमेटियों के लिए कई रियायतें देने की बात कही। लीला ग्राउंड में ईटीपी प्लांट नहीं लगाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। डीडीए द्वारा लगाई गए सिक्युरिटी शुल्क को 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर सिर्फ 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने की भी बात कही गई है। मुलाकात करने वालों में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सुभाष गोयल, कुलभूषण आहूजा, गुलशन विरमानी, महेन्द्र नागपाल व अन्य लोग शामिल रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-Hindustan Times

NEW DELHI
SATURDAY
AUGUST 06, 2022

New India Garden on Yamuna bank

The Central Vista axis extends from the Rashtrapati Bhawan, through the North and South Blocks, over Rajpath and to India Gate

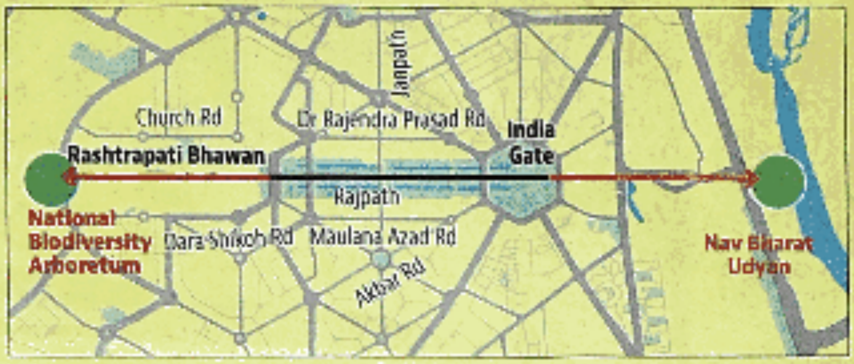

{ PART OF VISTA REVAMP }

Design of 'iconic structure' near Yamuna yet to get nod

Risha Chitlangia

rishachitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Central Public Works Department (CPWD) is yet to finalise the design for an "iconic structure" slated to be built at the New India Garden, or Nav Bharat Udyan, which will be developed on the banks of the Yamuna, said officials aware of the matter.

Originally proposed to be completed by August 15 this year to commemorate 75 years of India's independence, the structure is to be 134m tall, and is being planned to "realise the grand vision of Aatmanirbhar Bharat", said the Central Public Works Department's design brief when it launched a competition almost two years ago seeking entries for what the structure should look like.

CPWD began the competition in November 2020 and then July 2021. Though about 600 firms and individuals registered for the competition, the agency received 151 proposals till October 19,2021, which was the last date for submissions.

A senior CPWD official said that the design of the structure is in the process of being finalised, and a revised deadline for the New India Garden project is not yet in place.

> We received 151 entries in 2021. The finalisation of the design is under process.
>
> **SENIOR CPWD OFFICIAL**

"We received 151 entries in 2021. The finalisation of the design is under process. The revised timeline for completion of the New India Garden project has not been finalised yet," the official said, asking not to be named.

Spread over 25 acres, the New India Garden is proposed as part of the plan to extend the Central Vista axis from India Gate till the western bank of the Yamuna.

Located near the Old Fort, the garden will have infotainment facilities, a "sphere of unity", a walkway, an exhibit titled "Journey of India", a "tech dome", and an open-air theatre — apart from the "iconic structure".

The Central Vista project includes the redevelopment of Central Vista Avenue, the construction of a new Parliament building, the refurbishment of North and South Blocks, and the construction of new Central government offices, including a common Central Secretariat, and central conference facilities, among others.

Work on the Avenue is nearly complete, though no date has been finalised for its inauguration, officials have said. The new Parliament building, meanwhile, is 70% complete, Union minister of state for housing and urban affairs Kaushal Kishore informed Lok Sabha on Thursday, adding that the House will be ready by November 2022.

A senior Union ministry of housing and urban affairs ministry official, who asked not to be named, said, "Details for the iconic structure are being worked out."

Meanwhile, CPWD has approached the National Botanical Research Institute (CSIR-NBRI) in Lucknow for landscaping work on the garden, the official added.

Meanwhile, the Delhi Development Authority (DDA) is developing the AMRUT biodiversity park near the New India Garden on either side of the river, for which the CSIR-NBRI is also doing landscaping work on the theme of Independence.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER Hindustan Times ----DATED--- NEW DELHI SUNDAY AUGUST 07, 2022

Sisodia demands CBI probe against Baijal

Admits that govt incurred losses during changed excise rules, blames it on former LG

Sweta Goswami
letters@hindustantimes.com

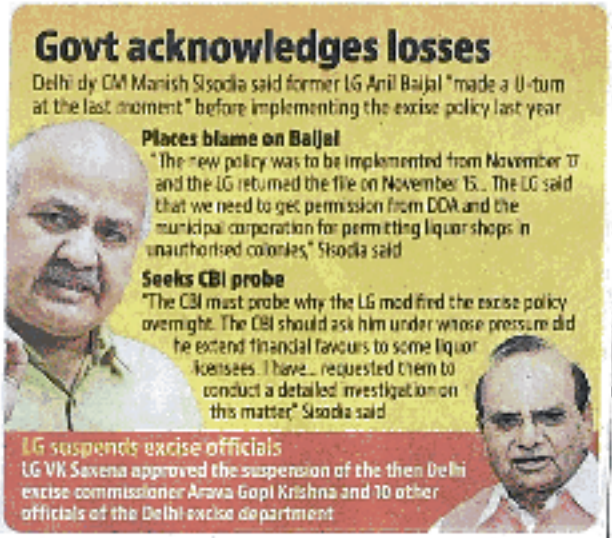

NEW DELHI: Delhi deputy chief minister Manish Sisodia on Saturday acknowledged that the Aam Aadmi Party (AAP) government in the national capital incurred losses worth "thousands of crores of rupees" under the new excise policy 2021-22, but blamed it on the previous Lieutenant Governor (LG), alleging that he "made a U-turn at the last moment" before implementing the new regime from November 17 last year.

The senior AAP leader, who is also Delhi's excise and finance minister, said he has written to the Central Bureau of Investigation (CBI) to probe the matter.

Addressing a press conference on Saturday from his residence in central Delhi's Mathura Road, Sisodia said the file on the 2021-22 excise policy went to then LG Anil Baijal twice before its implementation. In the first instance, Baijal sent back the file with certain suggestions and changes, which were then incorporated by the Delhi government, the deputy CM said.

"Under the new excise policy, 849 shops were to be opened across Delhi, including in unauthorised areas. The LG did not object to the proposal and approved it," Sisodia said.

"The file, after making the necessary changes as suggested by the LG, was sent for a second time in November first week. The new policy was to be implemented from November 17 and the LG returned the file on November 15, just 48 hours before the launch, asking us to make major changes to it. The LG said that we need to get per-

continued on →10

SISODIA

mission from the Delhi Development Authority (DDA) and the municipal corporation for permitting liquor shops in unauthorised colonies," Sisodia said.

The office of the LG and Baijal did not comment on the matter.

The Bharatiya Janata Party has alleged irregularities in the new excise policy and said that by withdrawing it, the AAP was trying to hide its corrupt practices.

"The CBI must probe why the LG modified the excise policy overnight. The CBI should ask him under whose pressure did he extend financial favours to some liquor licencees. I have sent the details of this illicit setup to the CBI and requested them to conduct a detailed investigation on this matter," Sisodia said.

Baijal was the Delhi LG when the Arvind Kejriwal government prepared the new excise policy, which was implemented on November 17, 2021.

Sisodia said that the suggestion to consult the DDA for opening liquor vends in unauthorised colonies was not mentioned by the LG in his previous remarks on the excise policy of 2021-22. It was only when the file pertaining to opening liquor shops after completion of the tender and allotment of licences to vendors went to the LG that he raised this new objection at the last moment, Sisodia said.

"Because of this, the Delhi government suffered losses worth thousands of crores of rupees, as close to 300-350 shops that were to open in unauthorised colonies could never operate under the new regime. As a result, the few companies who managed to open liquor shops in Delhi earned huge profits, while others suffered. The primary aim of the new excise policy was to put an end to the inequitable distribution of liquor shops, which could never be achieved because of the decision of the LG," Sisodia said, alleging that the LG's "sudden change in stance" could have been intentional in order to benefit certain private companies or individuals.

He added that Baijal changed his decision without discussing it with the cabinet and passed the order without the elected government's knowledge.

"In previous excise policies all the former LGs allowed opening of liquor stores in unauthorised colonies, the same was allowed by the LG in the new excise policy as well. But why was the policy modified so abruptly at the last moment? Why was the condition to get DDA-MCD NOCs added to it?"

Minutes after Sisodia's allegations on Saturday, the Raj Niwas said that current LG VK Saxena approved the suspension and initiation of "major disciplinary proceedings" against the then Delhi excise commissioner (IAS officer) Arava Gopi Krishna and DANICS officer Anand Kumar Tiwari (deputy excise commissioner), apart from three other ad hoc DANICS officers and four other officials.

The excise policy 2021-22, approved by the state cabinet chaired by chief minister Arvind Kejriwal in May last year, came under a lot of fire after the new LG referred it to the CBI for a probe, flagging alleged irregularities.

The policy has been withdrawn and extended just for a month to prevent a chaotic transition, and to ensure a smooth change to a system where only government-run stores will sell liquor from September 1.

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Saturday said that the AAP government used to say that the excise policy would revolutionise Delhi's liquor business and increase the state's revenue, but now, as soon as a CBI investigation has started, the AAP has started finding faults in its own policy.

"Now, when the heat of investigation has reached the AAP government in Delhi, they (Sisodia and Kejriwal) are busy finding a scapegoat. Sisodia is accusing the LG for making last-minute changes in the policy, but why is it that after 10 months of this policy being implemented in November last year, the AAP leaders are seeing flaws in it now," said BJP national spokesperson Sambit Patra.

"From the very first day, the Delhi government had accepted that the new excise policy is a milch cow. In this policy, liquor makers were also given licences for retail trade, as well as blacklisted companies were also given licences and groupers

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली, रविवार, 7 अगस्त 2022

शराब नीति को लेकर सिसोदिया ने लगाए आरोप, कहा- सीबीआई को भेजी जानकारी

पूर्व एलजी ने खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपना रुख बदला

वार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में आबकारी नीति को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब पूर्व उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर भी निशाना साधा है। सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि पूर्व एलजी ने खास दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदला। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

उपमुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने इससे जुड़ी पूरी जानकारी सीबीआई को भेजी है, जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उधर, बैजल ने फिलहाल इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नई आबकारी नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्रों समेत पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थीं। तत्कालीन उपराज्यपाल ने तब इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और इसे मंजूरी दे दी थी। लेकिन, नीति लागू होने से महज दो दिन पहले पिछले साल 15 नवंबर को तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपना रुख बदल लिया और शर्त लगा दी कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी से अनुमति लेनी होगी।

तत्कालीन उपराज्यपाल के रुख में बदलाव के कारण अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

भाजपा की भूमिका जांची जाए : मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि पूर्व राज्यपाल ने क्या किसी दबाव में अपना रुख बदला। क्या भाजपा का इससे कोई संबंध है।

बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने जब नई आबकारी नीति तैयार की थी, तब अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था। सरकार ने अब यह नीति वापस ले ली है और एक सितंबर से अपने उपक्रमों के माध्यम से पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें संचालित करने की तैयारी कर रही है।

मौजूदा एलजी वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान आबकारी नीति मामले में पूर्व एलजी पर निशाना साधा। • एएनआई

ये सवाल उठाए

सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने दुकानें खुलने के महज दो दिन पहले अपना निर्णय क्यों बदला। उन्होंने यह निर्णय खुद या किसी के दबाव में लिया, इससे किन दुकानदारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उन दुकानदारों ने इसके बदले किसे कितना फायदा पहुंचाया, इन सभी प्रश्नों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया है।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2022

बैजल ने अचानक बदली आबकारी नीति, राजस्व में हुआ नुकसान : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विवादों में घिरी नई आबकारी नीति को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को कठघरे में खड़ा किया है। सिसोदिया का दावा है कि अनधिकृत कालोनियों में शराब की दुकानें खोलने को लेकर बैजल ने 48 घंटे पहले रुख में बदलाव करते हुए नीति में बदलाव कर दिया। इसमें यह शर्त रखी कि इन इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए डीडीए और नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। सिसोदिया ने आबकारी नीति में अचानक किए गए इस बदलाव को लेकर सीबीआइ प्रमुख को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। शेष >> पेज 4

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया •

बैजल ने अचानक बदली...

सिसोदिया ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि नई आबकारी नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्रों सहित पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थीं। इस प्रस्ताव का अध्ययन कर तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बिना किसी आपत्ति के नीति को मंजूरी दी थी। इसके बाद 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति 2021-22 लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

आरोप है कि इससे ठीक दो दिन पहले यानी 15 नवंबर को उपराज्यपाल ने नीति में बदलाव कर दिया। इसमें यह शर्त लगा दी कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए डीडीए और दिल्ली नगर निगम से अनुमति लेनी होगी, जबकि इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें 2015 से खुल रही हैं। इससे इन क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं और सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ, जो दुकानें खुलीं, उनमें भारी भीड़ देखी गई। सिसोदिया ने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि बैजल ने अचानक नीति में बदलाव का यह निर्णय क्यों लिया, जिससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। पूर्व उपराज्यपाल ने क्या किसी दबाव में फैसला लिया और क्या भाजपा के किसी नेता का इससे कोई लेना-देना है।

तैयारी : दिल्ली में सभी लीज होल्ड संपत्तियां फ्री होल्ड करेगा डीडीए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में लीज होल्ड संपत्तिधारकों को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही बड़ी राहत देने जा रहा है। डीडीए की बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि दो माह में सभी लीज होल्ड संपत्तियां फ्री होल्ड करें।

इसके लिए जल्द ही डीडीए रोहिणी में कैंप लगाएगा। दिल्ली में लगभग 17 हजार से अधिक संपत्तियां हैं, जिन्हें फ्री होल्ड किया जाना है।

ऑनलाइन भी आवेदन: फ्लैट को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि आवंटी को डीडीए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। डीडीए के अनुसार, इससे काम तेजी और पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। ई-कन्वर्जन और ई-ईओटी के जरिए लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कन्वर्जन के साथ समय सीमा भी बढ़वा सकते हैं। इससे इन कामों में दलालों की भूमिका खत्म होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा।

जानें ऑनलाइन पंजीकरण से पेमेंट तक की प्रक्रिया

1. आवेदन के लिए डीडीए पब्लिक सर्विस के एलडी डिपार्टमेंट में पहले पंजीकरण कराना होगा।
2. इसके बाद मोबाइल-ईमेल पर ओटीपी मिलेगा। इससे आवेदक को लॉगइन करना होगा।
3. राशि का ब्योरा, कागजात आदि अपलोड करने के बाद ऑनलाइन ही पेमेंट भी करनी है।
4. पेमेंट के बाद ई-कन्वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाता है।

पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध

नई दिल्ली। दिल्ली वन विभाग ने डीडीए को अवगत कराया कि यमुना के बाढ़ संभावित मैदानी हिस्सों में करीब नौ हजार हेक्टेयर भूमि पौधरोपण के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि की कमी का मुद्दा बार-बार उठाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **THE SUNDAY EXPRESS,** AUGUST 7, 2022

Liquor wars: Govt trains guns on former L-G, Sisodia says he changed stance on vends

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 6

A WEEK after the Delhi government decided to scrap its new liquor policy, Deputy Chief Minister Manish Sisodia said he has written to the CBI requesting a probe into what he claimed was a sudden change in former L-G Anil Baijal's decision on opening vends in unauthorised areas. This caused "thousands of crores of losses" to the Delhi government, he alleged. Baijal did not respond to calls and messages seeking a comment.

Sisodia, who also holds the excise portfolio, had announced on July 30 that the new excise policy would be rolled back. This came after current L-G VK Saxena recommended a CBI probe into the new policy over alleged irregularities, and Delhi Police's Economic Offences Wing launched a probe into the excise department.

At a press conference on Saturday, Sisodia said: "In May 2021, the Cabinet passed the new excise policy. We said the number of liquor shops will remain the same. But in the earlier policy, shops were unevenly distributed — some wards had 25 shops, some had none... some malls had many shops. In the new policy, this principle was highlighted that there will be equitable distribution of shops, but the number of shops will not change. This was an important provision."

There were 849 shops earlier, and even under the new policy, the number of shops was to remain the same, as per Sisodia.

The policy was then sent to the L-G for approval and he made important suggestions for changes, Sisodia said. "All suggestions were accepted, and the new policy was sent to the L-G in June. He read it carefully and it was then passed. The policy said unequitable distribution will be stopped. In every ward, there will be two-three shops, including in unauthorised areas," Sisodia said.

Sisodia at a press conference on Saturday. *Amit Mehra*

But the L-G's office then changed its decision, he claimed.

"The L-G read the policy and then approved it. After this, tenders were issued... In the first week of November, the proposal to open shops was sent to the L-G, since they were to be opened from November 17 onwards, including in unauthorised areas. On November 15, the L-G laid down a new condition that to open shops in unauthorised areas, permission from the DDA and MCD is needed. When he read the policy, this condition was not laid down," he said.

"Why was this decision changed 48 hours before? Which shop owners made a profit? Did the L-G make the decision himself or under pressure from someone? I have written to the CBI asking for a probe," Sisodia said. "The real corruption was here... where the decision was changed."

Sisodia said that every year, shops were being opened in unauthorised areas even before the new policy kicked in: "Every year, these files were approved. This was approved even when the policy mentioned it. But when it went to the L-G office as a file to open the shops, the L-G office changed its stand."

"Because of this, shops were not able to open in unauthorised (areas). The new licensees went to court, which ordered that in unauthorised wards, licence fees be relaxed on a pro-rata basis and they be given a rebate. Because of this, the government faced thousands of crores of losses. Without discussing it with the Cabinet or government, the L-G changed his decision. The new excise policy would have brought revenue to the government, but instead, it caused losses because of this change in the L-G's stand," he claimed.

"The most important thing here is that some shops were allowed to open, others were not. Those allowed to open shops made profits. This was a deliberate attempt to ensure some vendors got profits and others faced losses," Sisodia added.

In his communication to the CBI, Sisodia wrote: "Through the new excise policy, in one financial year, the government was to get Rs 9,000 crore. In this financial year, with the new policy, the government was supposed to get Rs 3,713 crore, but got only Rs 2,352 crore in four and a half months."

Hitting out at the government, BJP national spokesperson Sambit Patra said at a press conference: "When the heat of the investigation has reached them, they are busy finding a scapegoat."

How Dilshad Garden started out as a slice of Lahore

ADRIJA ROYCHOWDHURY
NEW DELHI, AUGUST 6

DELHI REWIND
Tracing the capital's post-Independence history

WHEN SUSHIL Mishra (70) set out from his home in Unnao in 1968, he had a single purpose in mind — that of being a journalist in the national capital. With lofty dreams of being a news reader some day and meeting the high and mighty of Indian politics, he moved into his first home in the capital — a room in the Seemapuri slum of East Delhi. Mishra remembers those early days of struggle when he spent the days running from pillar to post to find a job in news offices, while the evenings went by in writing poetry.

"Everything about the city was such a shock for me. My room in Seemapuri did not even have a bathroom. Every morning, close to 30-40 people would queue up and then get into fights over the common bathrooms," he recalled.

As days went by, he saw his dream of being a journalist slowly slipping away, as he started taking up odd jobs in transport, construction and the like. On one such occasion, sometime in the late 1970s, he came across some officials from the Delhi Development Authority (DDA) who had started developing the nearby colony of Dilshad Garden. As he took up some contractual jobs with the DDA during this time, he saw with great enthusiasm the area around his slum developing with the best of facilities. "These were well-built flats, surrounded by parks and markets," he recalled.

Soon after, by 1985, Mishra had managed to earn a decent amount to rent his first accommodation in Dilshad Garden, a janta flat for which he paid Rs 250 as monthly rent. "For many living in the slums of Seemapuri, the making of Dilshad Garden signalled a new hope for their lives," he said. "Some of us who somehow made a little money hoped to get an accommodation here."

Dilshad Garden was in fact built at a time that ushered in a new phase in the development of the capital. Casually called 'Jamna paar' or the east side of the Yamuna, it was up until the 1970s considered unfit for development. "Originally East Delhi was avoided because about five or six kilometres eastwards from the river consisted of floodplains," explained Professor K T Ravindran, who served as head of urban design in the School of Planning and Architecture in Delhi and was former chairperson of the Delhi Urban Arts Commission.

Dilshad Colony was developed by the DLF. *Adrija Roychowdhury*

The first time the DDA turned its attention towards this area was during Sanjay Gandhi's urban renewal plan of the mid 1970s when close to 2 lakh people from the slums of Old Delhi were moved to the resettlement colonies like Jahangirpuri, Seelampur and Dakshinpuri, built by the authority in the peripheral areas of East Delhi.

It was only a few years later and with the political interest in cooperative housing societies that colonies like Dilshad Garden were developed in the area.

The original roots of Dilshad Garden, however, go back much further, to the 1940s, when the land here was first acquired by a barrister from Lahore, Diwan Khem Chand. Khem Chand had completed his education in England and was the man who conceived of the Model Town housing society in Lahore in 1921. He was an admirer of English urban planner Ebenezer Howard's idea of 'garden cities' and reproduced it in Model Town. He wished to bring the same architectural planning to Delhi's Dilshad Garden.

In 1940, Khem Chand founded the company, Housing in General Finance (HGF), which bought land for Dilshad Garden from the Tahirpur Estate Limited which had Rai Bahadur Madho Pershad as one of the directors. "By this time, people knew that land in and around Delhi was about to get valuable, so a lot of people were buying and consolidating property. Madho Pershad, who was a municipal commissioner and came from a banking family, had bought 600 acres of land in the east side and was just waiting to sell it when the chance arrived," explained Anish Vanaik, urban historian and clinical associate professor at Purdue University.

Vanaik noted that by 1950, HGF managed to sell off some 600 plots, by which time the scheme started failing and in the next few years the company collapsed. "The main reason is that they were not able to develop their plots into houses. They were trying to get the municipality to build roads, water and electricity, and the government was not keen on incurring costs for a private company's profits," he said.

After HGF failed in developing this area, a part of their land was bought by the Delhi Land and Finance (DLF) that had been developing several colonies in South Delhi by then. Indumati Sharma (92), who moved to Dilshad Colony developed by the DLF from Old Delhi in 1955, said that her family was forced to move to this area because they were asked to vacate their rented accommodation in Old Delhi and everywhere else in Delhi at that time was beyond their means.

Later in the 1980s, when the DDA took over the remaining plots and developed Dilshad Garden, there arose a marked distinction between the area built by the DLF and that which was built adjacent to it by the government. "Since we were a private colony, we still did not have access to basic amenities like electricity, water, roads. The DDA had all amenities that the middle class needed, and residents would look down on this area," said Sharma.

Sharma also recollected that since it was a flood-prone area, during the monsoons it would be common for her house to be submerged in several inches of water and they would have to frantically find space to keep valuables from getting spoiled.

The development of the DLF-built Dilshad Colony happened much later in the 2000s, and only with the intervention of the RWAs which pooled in money from all residents to build roads, sewers and get water connection. "The DDA refused to develop this area since it was a private colony and the DLF had already sold off its plots to residents by then and backed out from developing it any further," said Vijay Arora, a real estate developer living in Dilshad Colony.

Ravindran said that despite land conditions not being amicable, accessibility has historically been very good in Dilshad Garden. "It is bound on one side by the historic Grand Trunk Road that connected Central Asia to the Indian subcontinent. Later, with the coming of the DDA and the development of Noida and Ghaziabad, it was bounded on both sides by very important arteries," he said. "The Metro line too has played a significant role in developing this area. The red line, which was the first Metro line to be inaugurated in 2002 by then PM Atal Bihari Vajpayee, started out from the adjacent area of Seelampur."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI, AUGUST, 7, 2022
NAME OF NEWS........ -----DATED------------------

Sisodia blames ex-LG for excise loss, seeks CBI probe

New Delhi: Deputy CM Manish Sisodia alleged on Saturday that a former LG made it mandatory for liquor sellers to have the approval of the MCD and DDA when opening shops in non-conforming areas. This was done two days before the new excise policy came into force last year, he said, causing the state exchequer losses of "thousands of crores of rupees", **reports Atul Mathur**. Sisodia said he has written to the CBI to probe the LG's role in "favouring select liquor licensees... without the knowledge of the elected government". Anil Baijal was LG when the policy was implemented.

▸More on P 4

LG OKs suspension of 11 excise officials

LG V K Saxena Saturday approved the suspension of 11 excise officials for "deliberate lapses" in implementing the excise policy. **"An inquiry report by the directorate of vigilance establishes substantiated involvement of (deputy CM) Manish Sisodia in the excise scam,"** added sources in the LG's office, setting the stage for an escalation in confrontation between the Centre and Delhi government. **P2**

Former LG tweaked excise policy to favour some: Govt

Atul.Mathur@timesgroup.com

PTI

SISODIA SAYS
I am requesting CBI to investigate why the (then) LG backtracked on his own approval to the policy

New Delhi: At a press conference on Saturday, deputy CM Sisodia said, "The [former] LG made changes in the new excise policy just two days before the shops were to open in order to be able to extend special favours to a few liquor traders. The Delhi government had to bear a loss of thousands of crores due to his overnight step. The CBI must investigate the matter."

No immediate reaction was available from the LG's secretariat. Anil Baijal, who was the LG when the excise policy was implemented, did not respond to telephone calls and WhatsApp messages seeking his reaction.

The deputy CM claimed, "The LG gave some valuable suggestions when the cabinet sent the policy to him in May 2021. After making those changes, the cabinet again sent the policy to him in June 2021, which he approved. The policy had a provision for opening liquor shops in unauthorised areas. But the LG neither raised the issue of shops in unauthorised areas nor asked for a change."

Sisodia said the LG changed his stand when the file seeking permission for opening of the shops was sent to him in November. "The LG added a new condition on November 15 that the approvals of DDA and MCD were mandatory to operate shops in unauthorised areas," he said.

Sisodia said this U-turn was "unexpected and shocking" and vends couldn't open in unauthorised areas, forcing the licensees to move court. "The court directed the excise department not to take any licence fees from shops in unauthorised areas and also ordered a rebate on taxes and other relaxations, which caused a loss of thousands of crores to the exchequer while benefiting those who could open shops," he said.

The deputy CM said the LG's office had always approved of liquor shops in unauthorised colonies for many years. He added that when the LG was apprised of this, he did not change his stand but created a committee under the DDA vice-chairman, which did not have any outcome.

"I am requesting CBI to investigate thoroughly why the LG backtracked on his own approval to the policy," Sisodia said. In his letter to the CBI director, Sisodia accepted lapses in implementing the policy with the state government getting 38% less revenue than projected, but insisted it was pertinent to probe where and under whose direction such lapses happened.

Incumbent LG V K Saxena recommended a CBI investigation into procedural lapses in the excise policy in July. He also directed the chief secretary to probe the role of government officials in formulation and implementation of the policy, the report of which has been submitted. The Delhi government announced the withdrawal of the new excise policy from September 1 and reverted to the old regime.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 7 अगस्त 20 DATED-----------------

'चुनिंदा दुकानदारों के फायदे के लिए नई पॉलिसी में किए LG ने बदलाव'

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि कुछ चुनिंदा दुकानदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत से एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की दुकानों के खुलने से ठीक दो दिन पहले पॉलिसी में फेरबदल किया। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे सरकार को राजस्व के हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की। सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने अपना निर्णय 48 घंटे पहले क्यों बदला, इससे किन दुकानदारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, एलजी ने यह निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में, उन दुकानदारों ने इसके बदले किसे कितना फायदा पहुंचाया, इन सब प्रश्नों की जांच होनी चाहिए। इसे लेकर उपमुख्यमंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार को पत्र भी लिखा है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तब के उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू की गई थी। कैबिनेट की ओर से 15 अप्रैल 2021 को पास किए गए प्रस्ताव में एलजी ने कई बदलाव भी करवाए थे और उनकी मंजूरी से ही इसे लागू किया गया। सिसोदिया ने बताया कि इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या न बढ़ाते हुए उन्हें पूरी दिल्ली में समानता के आधार पर वितरित करने का प्रावधान रखा गया था। दिल्ली में पहले 849 दुकानें थीं, नई पॉलिसी में भी 849 दुकानें होनी थीं। पॉलिसी में ऐसे वॉर्ड की जानकारी देते हुए साफ लिखा गया था कि दिल्ली के हर वॉर्ड में, जहां पहले एक भी दुकान नहीं थी वहां भी कम से कम दो दुकानें खोली जाएं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मगर जब कारोबारियों ने लाइसेंस ले लिए और अनऑथराइज्ड इलाकों में दुकान खोलने के प्रस्ताव एलजी कार्यालय में पहुंचे तो दुकानें शुरू होने से ठीक दो दिन पहले यानी 15 नवंबर 2021 को एलजी ने एक शर्त लगाकर कहा कि अनऑथराइज्ड इलाकों में दुकान खोलने के पहले डीडीए और एमसीडी की मंजूरी लेकर ही दुकानें खोली जाएं।

सिसोदिया ने कहा कि एलजी को पता था कि डीडीए और एमसीडी मंजूरी नहीं दे सकते क्योंकि यह मामला अधिकृत क्षेत्र से संबंधित है और यहां दुकानें एलजी की मंजूरी से ही खुल सकती हैं। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में भी यही था। एलजी कार्यालय ने न तो कभी पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत ऐसी कोई शर्त लगाई थी और न ही नई एक्साइज पॉलिसी को पास करते वक्त, जिसके प्रावधानों में साफ-साफ एलजी की मंजूरी की बात की गई थी।

उठाए कई सवाल

- सिसोदिया ने की सीबीआई जांच की मांग, पूछा - 48 घंटे पहले क्यों बदली पॉलिसी
- पॉलिसी में फेरबदल से दिल्ली सरकार को राजस्व के हजारों करोड़ का नुकसान हुआ
- नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू की गई थी

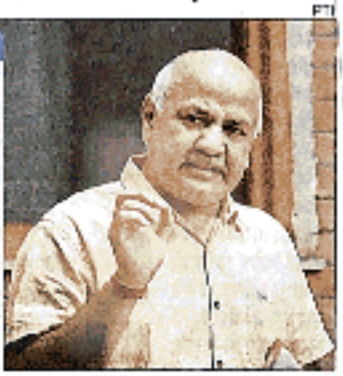

PTI

दिल्ली सरकार को हुआ भारी नुकसान

सिसोदिया का कहना है कि एलजी के इसी फैसले से दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। जब एक्साइज विभाग ने यह आकलन एलजी कार्यालय के सामने रखा कि अनऑथराइज्ड एरियाज में दुकानें नहीं खोलने देने से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान वर्तमान वित्तवर्ष में हो रहा है, तो भी सहमति नहीं दी गई बल्कि एक कमिटी बना दी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।

'आखिर किसके दबाव में बदली पॉलिसी?'

सिसोदिया के मुताबिक, एलजी ऑफिस की इस शर्त की वजह से लाइसेंस धारक कोर्ट में गए और वहां से यह फैसला अपने पक्ष में लेकर आए कि जितनी दुकानें नहीं खोली गईं, उनसे लाइसेंस फीस नहीं ली जाए, रिबेट दिया जाए। इससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह शर्त इसलिए लगाई गई ताकि कुछ खास लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस निर्णय से सालाना हजारों करोड़ का घाटा हुआ।

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
AUGUST 7, 2022

BJP perturbed by Sisodia's demand for probe: AAP

Times News Network

New Delhi: Aam Aadmi Party has accused Bharatiya Janata Party of playing "dirty politics" over the excise policy.

In separate press conferences, Kalkaji MLA Atishi and AAP chief spokesperson and MLA Saurabh Bharadwaj claimed that the BJP was "perturbed" with deputy CM Manish Sisodia's demand for CBI investigation into ex-LG's alleged role in sabotaging the new excise policy of 2021-22 and extending financial favours to a select few.

"The ex-LG's last-minute modification in the policy cost the Delhi government losses worth thousands of crores and ensured gains for a select few. Why is the BJP jumping into defence when we've sought an investigation against the ex-LG? Was BJP behind this huge scam?" Atishi questioned.

Earlier on Saturday, Sisodia in a press conference alleged that the then LG made it mandatory for licensees to seek DDA and MCD approval to operate from non-conforming areas, just two days before they were supposed to start opening their shops under the Delhi Excise Policy 2021-22.

The Kalkaji MLA claimed that the guidelines issued by the Central Vigilance Commission clearly state that any such modification of terms and condition after tender was a "befitting subject for vigilance inquiry".

"The former LG got to know which businessperson was running liquor shops in which area so he immediately changed terms of the tender. The speed with which the BJP jumped into the ex-LG's defence raises questions. Did the former LG add the MCD-DDA permission clause under BJP's pressure? Did any friends of BJP get any undue benefit out of the move? Do BJP leaders work in tandem with bootleggers that they want their business to thrive?" she further asked.

The only logical explanation, Atishi claimed, could be that the ex-LG, who was a BJP-led central government's nominee, indulged in financial wrongdoings to provide some favours to a select few. "It seems that the angle of corruption in this case doesn't stop at the former LG but goes all the way to the BJP's top leadership," she alleged.

Greater Kailash MLA Saurabh Bharadwaj claimed that the Delhi government's exchequer faced a 40% loss because the ex-LG prohibited liquor shops from being opened in 40% of the area of the city. "This led to bumper sales for a few shops besides the mafia. CBI comes under the BJP's central government itself. Why is BJP running away from investigation? The accusations have been made against the ex-LG and the defence is being presented by BJP leaders. Did BJP leaders, too, benefit out of the overnight modification?" he said.

AAP SAYS

CBI comes under the BJP's central government itself. Why is BJP running away from investigation?

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

NAME OF NEWSPAPERS------ ----------DATED------

भारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 8 अगस्त 2022

एलजी को व्यावहारिक नहीं लगा मास्टर प्लान–2041, ड्राफ्ट में होगा बदलाव

ड्राफ्ट की समीक्षा कर शहर को सुंदर बनाने के लिए जोड़े जाएंगे नए प्रविधान

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट से उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि यह राजधानी को अगले 20 साल तक स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए व्यावहारिक नहीं है। इसलिए एक बार फिर इस ड्राफ्ट की समीक्षा होगी और विभिन्न प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। नए ड्राफ्ट को तैयार करने में कुछ माह का समय लग सकता है। इस वजह से डीडीए के अधिकारी भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह प्लान केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय में कब तक अधिसूचित हो पाएगा। मास्टर प्लान-2021 गत वर्ष दिसंबर में ही समाप्त हो चुका है।

डीडीए सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना का मानना है कि बीते कुछ दशक में जिन नीतियों को लागू किया गया। उनसे दिल्ली में गंदगी बढ़ने के साथ ही झुग्गी बस्तियों व अनधिकृत कालोनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वह चाहते हैं कि इस बार ऐसी व्यवस्था बने, जिससे शहर को साफ सुथरा करने में मदद मिले। झुग्गी बस्ती वालों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। इसलिए अब दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यही वजह है कि एलजी मास्टर प्लान के मौजूदा ड्राफ्ट की समीक्षा कर कुछ बदलाव करना चाहते हैं। राजधानी का पहला मास्टर प्लान सन 1962 में बना था। इसके बाद 2001 और 2021 के मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में नाइट लाइट, वायु प्रदूषण, दिल्ली के विकास आदि को लेकर कई बातें शामिल की गई हैं।

डीडीए बोर्ड की बैठक में पिछले साल दी जा चुकी है ड्राफ्ट को मंजूरी: मास्टर प्लान-2041 के मौजूदा ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। नौ जून 2021 को इसका ड्राफ्ट जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। 75 दिन के अंदर डीडीए को इसे लेकर 33 हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। इन सभी आपत्तियों एवं सुझाव को डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनसुनवाई के माध्यम से सुना गया। अक्टूबर-नवंबर 2021 में इसके लिए 14 बैठकें हुईं। इन सभी बैठकों में विभिन्न लोगों, सिविल सोसायटियों, एनजीओ, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, फेडरेशन, प्रोफेशनल, सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों आदि की आपत्तियों और सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किए गए।

आवश्यक कदम » संपादकीय

प्रभावी प्रयासों के बिना सुंदर सड़कें नहीं बन सकतीं : एलजी

- एनडीएमसी की 'वन रोड – वन वीक' पहल का किया शुभारंभ
- प्राथमिकता के आधार पर 15 सड़कों को सुधारने का दिया निर्देश

तिलक मार्ग और भगवान दास रोड पर एनडीएमसी की 'वन रोड – वन वीक' पहल का शुभारंभ करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना (बाएं से दूसरे), साथ खड़े हैं एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल • सौजन्य : एनडीएमसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 'वन रोड- वन वीक' की योजना के तहत सड़कों को दुरुस्त करने और सुंदरीकरण का कार्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) में शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ (तिलक मार्ग, भगवान दास रोड) के फुटपाथ व पटरियों की मरम्मत के कार्य का शुभारंभ किया। एलजी ने इंटरलाकिंग ब्लाक बिछाने, पेड़ों की छंटाई, ग्रिल की पेंटिंग और रोड मार्किंग आदि जैसे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। एलजी ने कहा कि बिना प्रभावी प्रयास के सुंदर सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण और उनके उचित रखरखाव पर जोर दिया। फुटपाथ और सड़कों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर काम करने के लिए कहा।

उपराज्यपाल ने एनडीएमसी के अधिकारियों से कहा कि जिन 15 अन्य सड़कों में सुधार किया जाना है, उनका कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। तिलक मार्ग और अन्य सड़कों के सुधार कार्य को चरणबद्ध तरीके से करने के बजाय एक ही चरण में करें। इसमें फुटपाथों की मरम्मत, सफेदी, पेंटिंग, सुंदरीकरण, रेलिंग, रैंप, सेंट्रल वर्ज, बिजली के खंभों का उचित रखरखाव और सभी प्रकार के अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाना शामिल है। एलजी ने इन कार्यों की तस्वीरें एनडीएमसी की वेबसाइट पर भी डालने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को इन कार्यों की जानकारी मिल सके। इस दौरान एनडीएमसी के चेयरमैन अमरनाथ कुमार, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य कुलजीत चहल और सचिव विक्रम मलिक भी उपस्थित रहे।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए सतर्कता से करें कार्य: वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर स्थिति के लिए उपराज्यपाल ने सड़कों का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को कहा कि सड़कों, फुटपाथ और पटरियों के बीच मरम्मत का कार्य एक निश्चित समयसीमा में पूरा होना चाहिए, क्योंकि पीएम 2.5 के लिए 26 प्रतिशत प्रदूषण का कारण सड़कों और फुटपाथ व पटरियों से उड़ने वाली धूल है। उन्होंने पेड़ों की छंटाई करने के निर्देश दिए, ताकि पेड़ों की आयु में सुधार के साथ-साथ उन्हें एक सुंदर आकार दिया जा सके।

झुग्गियां हटाने के नोटिस का विरोध

■ विस, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने डीडीए के द्वारा विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर क्षेत्र में स्थित झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस भेजे जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है।

आप के एमसीडी सह-प्रभारी दीपक सिंगला के मुताबिक, डीडीए ने 18 अगस्त को यहां की सभी 150-200 झुग्गियां तोड़ने के लिए नोटिस दिया है, जबकि यहां पिछले 25-30 सालों से लोग रह रहे हैं। क्षेत्र के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने भी डीडीए को पत्र लिखकर झुग्गियों को बचाने की पहल करने के बजाय उन्हें खाली करवाने में सहयोग करने की बात कही है, ताकि डीडीए की कार्रवाई में कोई बाधा न आए। आम आदमी पार्टी ने मांग है कि झुग्गियां हटाने से पहले उनमें रहने वाले लोगों को रहने के लिए कोई अन्य जगह अलॉट की जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान ----------DATED-- नई दिल्ली सोमवार 8 अगस्त 2022

झुग्गी तोड़ने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। आम आदमी पार्टी की ओर से डीडीए पर कस्तूरबा नगर क्षेत्र की झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया है। साथ ही स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा है।

आप के निगम सह प्रभारी दीपक सिंगला ने रविवार को कहा कि डीडीए ने 18 अगस्त को सभी 200 झुग्गियां तोड़ने की जानकारी दी है। यहां पिछले 25 से 30 वर्षों से लोग रह रहे हैं। अब उन्हें बेघर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि यदि झुग्गियां हटानी हैं तो पहले लोगों को रहने के लिए अन्य स्थान दिया जाए।

अब दिल्ली में रामलीला मंचन के लिए मुफ्त बिजली की मांग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए के निर्देशों के चलते इस साल रामलीलाओं के आयोजन में आ रही दिक्कतें दूर होने के बाद रामलीला आयोजकों ने अब रामलीला के मंचन के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की मांग की है। रविवार को रामलीला महासंघ की तरफ से आयोजित एक आभार सम्मेलन में कहा गया कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार कांवड़ शिविरों और हज कैंप के लिए बरसों से फ्री बिजली मुहैया कराती आ रही है, उसी तरह रामलीलाओं के आयोजन के लिए भी मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। सम्मेलन में रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का सम्मान किया। साथ ही, दिल्ली के उप-राज्यपाल का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया।

सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा,सरकार को लीला कमिटियों को भी मुफ्त बिजली देनी चाहिए

इस अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि रामलीला आयोजकों से सरकार कमर्शल आधार पर बिजली का बिल वसूलती है, जबकि लीला के आयोजक चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्रीराम की लीला का निःशुल्क मंचन करते हैं। ऐसे में सरकार को लीला कमिटियों को भी मुफ्त बिजली प्रदान करनी चाहिए। सम्मेलन में ऐलान किया गया कि दिल्ली को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से सभी प्रमुख रामलीला कमिटियां इस साल लीला का मंचन देखने आने वाले दर्शकों को निशुल्क पौधे बांटेंगी। साथ ही लीला स्थल पर प्लास्टिक के बैनर, झंडे इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे और प्लास्टिक बैन के प्रति दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जाएगा।

फैक्टरी लगाना नहीं रहेगा आसान

कवायद

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में फैक्टरी लगाना चाहते हैं तो आपके के लिए लाइसेंस लेना मुश्किल होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से फैक्टरी लाइसेंस लेने के लिए कन्वेयंस डीड (मालिकाना हक) को अनिवार्य करने जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जहां प्लॉट का आवंटन डीडीए की ओर से किया गया है।

दरअसल, डीडीए आने वाले दो महीनों में लीज होल्ड की सभी संपत्तियों को फ्री होल्ड में तब्दील करने जा रहा है। रिहायशी क्षेत्र में खुली ज्यादातर फैक्टरी के मालिकों के पास लाइसेंस नहीं हैं। फैक्टरी या इंडस्ट्री खोलने के लिए भी अलग-अलग दो तरह के प्लॉट होते हैं। इसमें एक लीज होल्ड जिसे डीडीए, डीएसआईआईडीसी या दिल्ली सरकार ने आवंटित किया है। दूसरा फ्री होल्ड, जिसका मालिक शख्स खुद होता है। नई प्रक्रिया के तहत किसी का अपना प्लॉट है, तो उसे लीज होल्ड की कॉपी के बदले मालिकाना हक की कॉपी लगानी होगी। बाकी प्रक्रिया और दस्तावेज उसी तरह के होंगे। रिहायशी क्षेत्र में फैक्टरी खोलने के नियम-कायदे अलग हैं।

तमाम दस्तावेज जमा करने के बाद लाइसेंस मिलेगा

1. डीडीए, डीएसआईआईडीसी या दिल्ली सरकार से प्लॉट आवंटन की मालिकाना हक की कॉपी लगेगी।
2. सेंक्शन बिल्डिंग प्लान और साइट प्लान आदि की जानकारी आदि भी देनी होगी।
3. नोटरी से सत्यापित शपथपत्र. इंडस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी चाहिए।
4. फायर एनओसी भी देनी होगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिन में लाइसेंस जारी होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---DATED---------------------

नई दिल्ली। शनिवार • 6 अगस्त • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

रामलीला कमेटियों को 5 लाख रुपए अग्रिम जमा कराने का आदेश रद्द

रामलीला ग्राउंड के आवंटन के साथ लगी शर्तों में दी छूट

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ एलजी से मिले रामलीला महासंघ के पदाधिकारी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रामलीला कमेटियों को राहत देते हुए 5 लाख रुपए अग्रिम धरोहर राशि जमा कराने से छूट दे दी है। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर ईटीपी प्लांट लगाने की शर्त को हटाते हुए सफाई शुल्क घटाकर 2.75 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया है। शुक्रवार को रामलीला महासंघ के पदाधिकारी प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार, सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में उप-राज्यपाल से मिले और अपनी बात रखी। रामलीला महासंघ के प्रतिनिधियों में महासचिव सुभाष गोयल, गुलशन विरमानी, डॉ. महेंद्र नागपाल, धीरज गुप्ता समेत अन्य कमेटियों के भी पदाधिकारी और डीडीए, दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी एवं दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे।

महासंघ के मुताबिक राजधानी में 650 से अधिक जगहों पर रामलीला होती है। पदाधिकारियों ने कहा कि डीडीए की ओर से लगाई गई शर्तें रामलीला कमेटियों के लिए आसान नहीं है। उप-राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि इस बार उन्हें आयोजन स्थल पर ईपीटी प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही डीडीए द्वारा सुरक्षा शुल्क के नाम पर 66 रुपए प्रति वर्गमीटर की राशि अग्रिम जमा कराने की शर्त में बदलाव कर दिया। आयोजकों को अब केवल 15 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से यह शुल्क जमा कराना होगा। इसके साथ ही सफाई शुल्क की दर भी घटाकर 2.75 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। उप-राज्यपाल ने 5 लाख रुपए की राशि अग्रिम जमा कराने के आदेश को निरस्त कर दिया। उप-राज्यपाल ने डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए वन विंडो प्रणाली लागू की जाए।

अमर उजाला | शनिवार, 6 अगस्त 2022

रामलीला मंचन से संबंधित कई विभागों की शर्तें कम

श्रीरामलीला महासंघ ने कई समस्याओं से उपराज्यपाल को कराया अवगत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी में लगभग 650 जगह रामलीला मंचन से जुड़ी समस्याओं से श्री रामलीला महासंघ के पदाधिकारियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अवगत कराया है। उपराज्यपाल ने उनकी बातें सुनने के बाद डीडीए की ओर से जमानत शुल्क 66 रुपये प्रति मीटर से घटाकर 15 रुपये मीटर और ईटीपी प्लांट की शर्त निरस्त करने का वादा किया।

उपराज्यपाल ने डीडीए, एमसीडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया कि रामलीलाएं बहुत ही उत्साह, हर्षोल्लास के साथ संपन्न होनी चाहिए। सभी विभाग रामलीला मंचन के लिए स्वीकृति देने के लिए सरल तरीका निकालें।

श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि डीडीए, दिल्ली पुलिस, एससीडी, दिल्ली छावनी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी की एनडीएमसी, एएसआई व अन्य विभाग रामलीलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं। श्री रामलीला महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा के अलावा अन्य लोग थे।

पंजाब केसरी DELHI ▸ 6 अगस्त, 2022 ▸ शनिवार

'नहीं देने होंगे अब सुरक्षा राशि के रूप में 10 लाख'

दिल्ली धार्मिक महासंघ ने रामलीला आयोजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर एलजी से की मुलाकात

खास बातें...

- रामलीला आयोजन के लिए सभी विभागों से एनओसी अब दिल्ली पुलिस स्वयं लेगी : वर्मा

▸▸ एलजी से मुलाकात के दौरान कुलभूषण आहूजा, आदेश गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह, अशोक गोयल व अन्य।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को दिल्ली धार्मिक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ झंडेवालान मंदिर के सचिव एवं दिल्ली प्रांत के संघचालक कुलभूषण आहूजा एवं पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर रामलीला के आयोजकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को उनके सामने रखा। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी के स्पेशल अधिकारी एवं आयुक्त, डीपीसीसी के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी संदर्भ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आदेश गुप्ता ने नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद प्रवेश साहिब सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में 650 रामलीलाओं के आयोजकों के सामने कोरोना काल के बाद आयोजन में कठिनाई हो रही थी, इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपराज्यपाल ने इन पर कई सकारात्मक निर्णय लिए। प्रेसवार्ता में प्रदेश भाजपा मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना भी उपस्थित रहे। गुप्ता ने बताया कि डीडीए द्वारा रामलीला आयोजन के स्थानों के लिए रेट पहले 66 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर लिया जाता था। उसे उपराज्यपाल ने घटाकर 15 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर कर दिया। साथ ही एनजीटी द्वारा खाना न पकाने, सिक्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपये देने एवं ईटीपी प्लांट लगाने के लिए रामलीला आयोजकों को बाध्य किया जाता था, लेकिन उपराज्यपाल ने उसमें बदलाव किया ताकि आयोजकों से सुरक्षा राशि के रूप में जो 10 लाख रुपये मांगे जा रहे थे, उन्हें अब यह राशि जमा नहीं करनी होगी। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो रामलीला के आयोजनों के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था अब उसका सरलीकरण किया जा रहा है और आयोजकों को ऑनलाइन लाइसेंस रामलीला शुरू होने से पहले ही मिल जाएंगे। दिल्ली धार्मिक महासंघ के महामंत्री अशोक गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल ने रामलीलाओं के मंचन का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक करने के लिए स्पेशल सीपी को आदेश जारी कर दिए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी ▸ 7 अगस्त, 2022 ▸ रविवार

आबकारी नीति पर एलजी ने रुख क्यों बदला

सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान

पंजाब केसरी/नई दिल्ली

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। सिसोदिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस मामले से जुड़ी जानकारी सीबीआई को भेज दी है और दिया कि मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। बैजल ने इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिसोदिया ने कहा, ''नयी आबकारी नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्रों समेत पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थीं। तत्कालीन उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और इसे मंजूरी दे दी।'' उन्होंने आरोप लगाया कि नीति लागू होने से दो दिन पहले पिछले साल 15 नवंबर को तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपना रुख बदल लिया और शर्त लगा दी कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से अनुमति लेनी होगी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा, ''तत्कालीन उपराज्यपाल के रुख में बदलाव के कारण अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

11 अफसर निलम्बित किए एलजी ने

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में 'गंभीर चूक' को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपीकृष्ण और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के दानिक्स कैडर के तीन तदर्थ अधिकारियों और छह अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल ने आबकारी नीति के कार्यान्वयन में 'संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई कथित गंभीर चूक' को देखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसमें 'निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट-टेंडर लाभ प्रदान करना' शामिल है। उपराज्यपाल सक्सेना ने डीओवी की ओर से दायर एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

अमर उजाला नई दिल्ली | रविवार, 7 अगस्त 2022

पौधरोपण के लिए 9 हजार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध

अमर उजाला ब्यूरो

वन विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर दी जानकारी

पौधरोपण के लिए जमीन की कमी का उठाया था मुद्दा

नई दिल्ली। दिल्ली के यमुना बाढ़ इलाके में पौधरोपण के लिए नौ हजार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का उपयोग राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत नदी पारिस्थितिकी को बढ़ाने और प्रतिपूरक पौधरोपण के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी वन विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दी है।

बीते दिनों डीडीए ने पौधरोपण के लिए भूमि की कमी का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में वन विभाग ने डीडीए को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि विभाग ने केंद्र के 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प की परियोजना को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण किया है। इससे पता चला है कि यमुना के बाढ़ इलाकों में पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध है। परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में संरक्षण, पौधरोपण, जलग्रहण उपचार, पारिस्थितिक बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका में सुधार, रिवरफ्रंट और इको-पार्क विकसित करके आय सृजन और इको टूरिज्म आदि बिंदु शामिल हैं।

केंद्र के मुताबिक, डीपीआर में प्रस्तावित गतिविधियों से हरित आवरण को बढ़ाना, मृदा अपरदन को कम करने, जल स्तर का पुनर्भरण करने और कार्बन डाई ऑक्साइड को कम करने में मदद मिलेगी। वन विभाग ने लिखा है कि मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, यमुना और ओजोन के क्षेत्र के कायाकल्प को पौधरोपण के लिए भूमि का विश्लेषण किया गया है। ओजोन में कम से कम 5,532 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, वहीं यमुना के बाढ़ के मैदानों में उपलब्ध क्षेत्र लगभग नौ हजार हेक्टेयर है। 2,480 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त है, जिस पर 2009 से अतिक्रमण था। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यदि बाढ़ के मैदानी इलाकों में पौधरोपण किया जाता है, तो दिल्ली का हरित आवरण वर्तमान में 23 फीसदी से बढ़कर 2025 तक 25 फीसदी हो सकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक भास्कर नई दिल्ली, रविवार 7 अगस्त, 2022 ...TED

उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई

पूर्व आबकारी आयुक्त आरव समेत 11 अफसर निलंबित

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व एलजी बैजल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आबकारी नीति में चूक और भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण समेत 11 अफसरों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मुख्य सचिव नरेश कुमार और सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद हुई है। मुख्य सचिव ने 8 जुलाई को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बड़ी प्रक्रियात्मक चूक और आबकारी विभाग पर मंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर अनुचित लाभ देने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को लेकर पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से लिए गए फैसले पर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को पहले पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में फैसला रद्द कर दिया। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। यह फैसला क्यों लिया गया? मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। नई आबकारी नीति 2021 में लागू की गई थी, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दी।

नवंबर में आई नई नीति पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल

बीते साल नवंबर में दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की बिक्री के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। इस नीति के तहत पुरानी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। शराब की सरकारी दुकानें तक बंद कर दी गई थीं और नई नीति से नए टेंडर जारी कर निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। दिल्ली बीजेपी के नेता इसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। नई आबकारी नीति में अनियमितता की शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को आदेश दिया था कि नई आबकारी नीति बनाने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सूचित करें।

सिसोदिया का आरोप...
नई पॉलिसी लागू होने से दो दिन पहले बदला फैसला

सिसोदिया ने दावा किया कि पूर्व एलजी ने पहले अनधिकृत क्षेत्र में दुकानें खोलने पर आपत्ति नहीं की थी, लेकिन नीति लागू होने से दो दिन पहले उन्होंने अपना रुख बदल लिया और शर्त लगा दी कि अनधिकृत क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी से अनुमति लेनी होगी। सिसोदिया के अनुसार, नई नीति में पूरी दिल्ली में बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था।

भाजपा का पलटवार...
सिसोदिया ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया और केजरीवाल पर पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि उपराज्यपाल ने संविधान के अनुसार कार्रवाई की है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए थे। अब जब घोटाले सामने आ रहे हैं, सीबीआई और ईडी छापेमारी कर रही है तो आप सरकार मामले को दबाने में लग गई है। मनीष सिसोदिया ने सफेद झूठ बोला है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

निगम : पीपीई किट, ग्लव्स इत्यादि दिए
कूड़े के निस्तारण हेतु एमसीडी ने कूड़ा बीनने वालों के साथ की बैठक

नई दिल्ली | दिल्ली नगर निगम ने स्त्रोत पर कूड़े के निस्तारण हेतु ईस्ट ऑफ कैलाश के पॉकेट जी में कूड़ा बीनने वालों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य कूड़ा बीनने वालों को गीले, सूखे एवं घरेलू हानिकारक कूड़े का स्त्रोत पर निस्तारण एवं गीले कूड़े को कॉलोनी के नए बने निर्धारित कंपोस्ट प्लांट में डालना, प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक के लिए कूड़ेदानों में एकत्रित करना एवं एमसीडी, आरडब्ल्यूए एवं डीडीए, एलआईसीएल के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करना के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर बैठक में सम्मिलित सभी नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। निगम द्वारा आयोजित बैठक में कूड़ा बीनने वालों को पीपीई किट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ग्लव्स एवं टोपियां भी वितरित की गईं। जीरो वेस्ट कॉलोनी अभियान को आरंभ करने के पीछे निगम का उद्देश्य स्त्रोत पर ही ठोस कूड़े का निस्तारण करना है जिससे कि इसके ढुलाई की मद में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 7 AUGUST, 2022

Excise policy: Sisodia blames ex-Delhi L-G of changing stance

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Former Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal had unilaterally brought a last-minute change in the excise policy which caused huge revenue loss to the city government and windfall gains to some vendors, Deputy Chief Minister Manish Sisodia claimed on Saturday, demanding a CBI probe into it.

Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia addresses a press conference, in New Delhi, on Saturday PC/NAVEEN SHARMA

Addressing a press conference, Sisodia said he has sent the details to the Central Bureau of Investigation (CBI) and hoped that the agency will conduct a thorough probe into the charges. He also alleged that the real corruption happened when Baijal brought in some key changes in the policy without holding any consultation with the Arvind Kejriwal dispensation.

The AAP minister also questioned under whose pressure did he make the modifications in the policy.

Baijal was the LG when the city government prepared the new excise policy. The government had last week announced that it would revert to the old excise policy of running liquor vends.

Sisodia has also written to CBI director Subodh Kumar Jaiswal, detailing the "multiple abrupt lapses" on part of the former L-G right before the opening of the liquor vends that caused "losses of thousands of crores to the government."

Continued on P4

Excise policy

"The former Delhi L-G made changes in the new excise policy two days before shops were to open so he could extend special favours to a few liquor traders. The Delhi government had to bear a loss of thousands of crores due to his overnight step," he said at the press conference.

Claiming Baijal had carefully examined and studied the excise policy and had even suggested changes as per his understanding, the Delhi deputy chief minister questioned, "Then why did he modify the policy 48 hours before shops were to be opened?

"Under the old excise policy, all the former L-Gs allowed opening of liquor stores in unauthorised colonies, then why was the policy modified so abruptly? Why were no objection certificates (NOC) from DDA-MCD added to it?" he asked.

"The government lost revenue worth thousands of crores because the then L-G changed his decision without discussing it with the Cabinet, and passed the order without the elected government's knowledge," he added.

Detailing the timeline of the events, Sisodia said the new excise policy was passed in May 2021. Under this, the number of liquor shops was the same as it was as per the old excise policy — 849. However, these 849 shops were unevenly distributed under the old policy.

"Some areas or wards had as many as 25 shops, while some areas had no shops. Some shopping malls had 10-15 shops or even 20 shops, while few markets did not have any shops. To change this, we kept a principle of equitable distribution of shops in the new excise policy.

"We had duly emphasised that the number of shops would not increase, but would be evenly spread. This was being done to avoid hooch tragedy or any other mishap or irregularity," he explained.

The minister said when the cabinet sent the policy to the Lieutenant Governor for approval in May 2021, he read the policy in detail and gave "valuable suggestions to make changes in a number of provisions which were duly accepted by the Cabinet".

"The Cabinet made those changes and again sent the policy to the L-G in June 2021 and he approved it," said Sisodia.

"At the time of passing this policy, the L-G neither raised the issue of opening shops in unauthorised areas nor gave any suggestion to make a change in it. After his approval, the government issued the tenders under the policy. The licensee took the tender at a rate which was 25 per cent higher than the expected rate by the government," he said.

Sisodia said the shops were supposed to open from November 17 last year. "The L-G added a new condition on November 15 that approval of Delhi Development Authority (DDA) and Municipal Corporation of Delhi (MCD) was mandatory in order to open shops in unauthorised areas," he said.

"He (Baijal) added this condition because he knew that it meant permission from L-G's office for which the file would again come back to him. This U-turn was unexpected and shocking because of which shops could not get open in unauthorised areas," he added.

The new licensees went to the court which directed them not to take any licence fees from shops in unauthorised areas. The court also ordered them to give a rebate on taxes and other relaxations as well.

The new excise policy would have resulted in massive gains to the exchequer, but what happened was exactly opposite, the AAP minister ruled.

Meanwhile, Aam Aadmi Party (AAP) chief spokesperson Saurabh Bharadwaj hit out at the BJP for coming out in defence of the former L-G.

"What is your problem if CBI investigates the matter and looks into the questions raised by the deputy chief minister? Why are you scared?" he asked.

"The BJP should not try to save the former L-G. When we are welcoming the CBI probe, they (BJP) should also welcome it," Bharadwaj added.

Delhi L-G

including, "irregularities in finalising the tender and extending post-tender benefits" to select vendors, they said.

According to sources, the 11 officials against whom suspension and disciplinary action have been approved include the then assistant Excise Commissioners Pankaj Bhatnagar, Narinder Singh and Neeraj Gupta.

The action was taken by Saxena based on an inquiry report filed by the Directorate of Vigilance (DoV).

Sources claimed the report contained proof of irregularities that were provided to the DoV by the finance and the excise departments, both under the charge of Deputy Chief Minister Manish Sisodia.

The inquiry report brings out the blatant violation of procedures, deliberate misinterpretation and subversion of basic government financial rules to provide benefit to licencees "obviously for a quid pro quo", they said.

"From the formulation of the tender document to the award of tenders, undue return of earnest money deposit worth Rs 30 crore, waiver of licence fee worth Rs 144.36 crore to allowing additional liquor vends to be opened by chosen licencees, the entire episode stinks of corruption and connivance," sources alleged.

According to the report, the excise department officers equated the successful tenderer selected for the airport zone to get NoC from the authorities to open vends there with unsuccessful bidders to be refunded Rs 30 crore earnest money deposit (EMD).

"The deputy chief minister, through his note in July 2021, decided the EMD should be refunded to the H1 bidder who had failed to obtain a no objection certificate from the airport authority," sources said citing the report.

Sisodia had alleged the Delhi government suffered losses worth thousands of crores of rupees since then LG Anil Baijal on November 15, 2021, changed his stand putting a condition that DDA and MCD approval were needed for opening liquor vends in non-conforming areas in the city.

Baijal had approved the proposal to allow liquor vends as per Excise Policy 2021-22 that was implemented on November 17, 2021, he had said.

Sisodia asserted the need for a probe to find out why and under what pressure the then LG changed his stand and if there was a role of any BJP leaders in it.

However, the enquiry report said the officers of the Excise department allowed waiver on tendered licence fees of Rs 144.36 crore for closure of retail vends due to Omicron-related issues.

This was done although no such specific provision for compensation in form of reduction in tendered licence fees was available in the tender document, it stated.

"However, the officers moved ahead and the minister in-charge vide direction dated February 1, 2022, directed to provide pro-rata licence fee relief to each licensee of the closed vends," sources said quoting the report.

The Finance department had underlined that the proposed changes in the Excise Policy 2021-22 were "prima facie wrong" and required the L-G's approval. But Sisodia "blocked the note to this effect and returned the file to the finance secretary", sources said quoting the enquiry report. "It was observed that modifications were carried out in the proposed Excise Policy as well as terms and conditions of the licences such as the requirement of a minimum turnover for wholesale licence reduced to Rs 150 cr per annum from Rs 250 cr, revision in minimum carpet area of super premium vends delinking retailers from wholesalers and manufacturers, net worth criteria for applying for retail zones, etc," sources said citing the report.

Quoting the observations of the report, they alleged the excise department officials "brazenly indulged in cartelisation, awarding tenders to blacklisted companies and illegally allowing manufacturers to get retail licences" by "illegally amending" the Excise Policy.

A Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry has already been recommended by the LG into the alleged violation of rules and procedural lapses in the implementation of the Excise Policy 2021-22.

Under the policy, implemented on November 17, 2021, private firms were issued retail licences for 849 liquor vends across the city divided into 32 zones. The policy has now been withdrawn by the Aam Aadmi Party government.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------DATED-----------------

THE HINDU
SUNDAY, AUGUST 7, 2022

Govt. alleges corruption in decision by former L-G

Sisodia seeks CBI probe, says Baijal tweaked excise policy without consulting them

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Saturday alleged "corruption" by the office of the former Lieutenant-Governor, which brought a change in the Delhi Excise Policy 2021-22 without consulting the government, causing huge revenue loss to the exchequer and windfall gains to some vendors.

He sought a CBI investigation into the matter and alleged the role of BJP leaders in the "corruption".

Mr. Sisodia, who also holds the Excise portfolio, said, "Under the policy [Delhi Excise Policy 2021-22], it was said that liquor vends will also open in unauthorised colonies; there was no opposition [from the L-G] and it was passed. On November 15 [last year], two days before vends were supposed to open, the L-G put a new condition that liquor vends in unauthorised colonies should have permission from the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi," Mr. Sisodia said.

He said due to this sudden change in decision, vendors whose shops opened in authorised colonies benefited and those whose shops were not opened, as they were in unauthorised colonies, lost crores of rupees.

"There should be an investigation into whether the L-G took the decision on his own or under pressure from someone and who benefited from this. I have written to the CBI," Mr. Sisodia said.

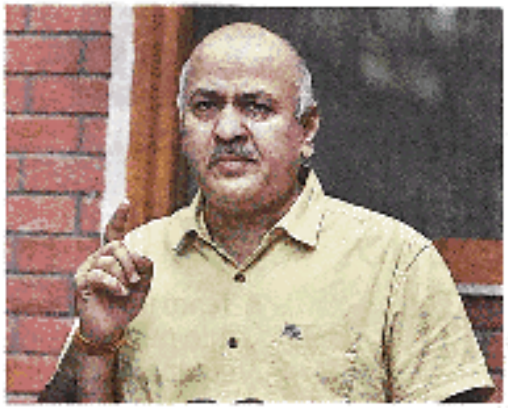

Deputy Chief Minister Manish Sisodia addressing a press conference in New Delhi on Saturday. •SHIV KUMAR PUSHPAKAR

'Special favours'

He alleged that former L-G Anil Baijal made the change in the policy to extend "special favours" to a few liquor traders and the CBI must investigate the matter.

"The policy would have resulted in massive gains to the exchequer but what happened was exactly the opposite," he said. "The government lost revenue worth thousands of crores because the L-G changed his decision without discussing it with the Cabinet and passed order without elected government's knowledge," the Minister added.

When asked why the issue is being raised after so many months, Mr. Sisodia said they went through all the files on the new excise policy to understand the issue now.

Later in the day, AAP also attacked the BJP over the development and accused it of running away from the CBI investigation now.

> There should be an investigation into whether the L-G took the decision on his own or under pressure from someone and who benefited from this. I have written to the CBI
>
> MANISH SISODIA, Deputy Chief Minister

Change in attack

On July 22, Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena recommended a CBI probe into the Delhi Excise Policy 2021-22, bringing Mr. Sisodia in the direct line of fire.

Mr. Sisodia's demand for a CBI probe and admission of revenue loss is a new line of offence on AAP's part on the excise policy, which has turned into a political controversy since the L-G's intervention. The day the L-G recommended the CBI probe, Chief Minister Arvind Kejriwal accused the political "Opposition" of embarking on a "malicious slander campaign" against Mr. Sisodia.

The Opposition, the Chief Minister said, sought to stall AAP's growing political clout in the country through such allegations, especially after the party formed the government in Punjab.

AAP leaders had said there was no corruption in the new excise policy and it had generated huge profit for the exchequer in a few months.

On July 26, AAP leaders alleged that the BJP has closed about 200 liquor vends to allow the sale of spurious liquor and make money from it. This was reiterated by the party on different occasions.

AAP looking for scapegoat for own wrongdoings: BJP

'Why are they seeing policy flaws now?'

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The Bharatiya Janata Party (BJP), in its latest showdown with the Aam Aadmi Party-led Delhi government over the now-scrapped excise policy, accused Chief Minister Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia of having perpetrated a scam worth crores through it.

The party said Mr. Sisodia's allegations of corruption in the policy being the handiwork of former Delhi Lieutenant-Governor Anil Baijal were an attempt to look for a scapegoat as a CBI investigation into the "scam" was more than likely to put the Deputy Chief Minister in the dock.

'Favours to liquor mafia'

"Now that the heat of investigation has reached them, they are looking for a scapegoat. Sisodia is accusing the L-G of last-minute changes in the policy and AAP leaders are seeing flaws in it after 10 months of its implementation in November last year," BJP national spokesperson Sambit Patra said.

"Kejriwal and Sisodia will have to answer why they waived off ₹144 crore to the liquor mafia. They extorted money on a large scale by making the liquor policy only for the benefit of the mafia and are accused of contesting elections in Punjab by spending crores of rupees thus earned," he said.

Delhi BJP president Adesh Gupta said they had been opposing the new excise policy from day one since it allowed liquor shops to open even in areas where they were banned. "When all the allegations levelled by us are being proven and the CBI has started investigating them, Sisodia has also started seeing flaws in his own policy," Mr. Gupta said.

Leader of the Opposition in the Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri said he had been demanding that the Delhi government should not go ahead with the "wrong policy" and had even raised the issue in the Assembly. "But the Kejriwal government was bent on violating the law and master plan for its own benefit. Today it has become clear that the new policy was wrong. I had challenged that it would be proved wrong that is what is happening now," Mr. Bidhuri said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- sunday pioneer
NEW DELHI I SUNDAY I AUGUST 7, 2022

Sisodia seeks CBI probe into ex-LG's role in Excise Policy

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia addresses a press conference in New Delhi on Saturday PTI

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Accusing former Lieutenant Governor Anil Baijal of creating a mess in the new excise policy, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has written to the Central Bureau of Investigation seeking a probe against the former as to why he changed his stand on the opening of liquor shops in unauthorised colonies just 48 hours before the launch of the policy.

Sisodia claimed that the sudden change in the then LG's stand led to "thousands of crores" of losses to the Government exchequer as close to 300-350 liquor shops that were supposed to open in unauthorised colonies could not be opened.

Addressing a Press conference here at his Mathura Road residence, Sisodia said he has sent the details of the matter to the CBI and asserted that there should be a probe into it.

"Delhi Lieutenant Governor made changes in the new excise policy two days before shops were to open so he could extend special favours to a few liquor traders.

"The CBI should also find out if the decision was taken independently and without his pressure or coercion. I am fully optimistic that the CBI will investigate this matter fairly," he said.

This is the first time that the AAP Government has acknowledged that it has incurred losses worth "thousands of crores" of rupees under the new excise policy.

Continued on Page 2

Sisodia for...

From Page 1

But blamed it squarely on the LG, who he alleged "made a U-turn at the last moment" before implementing the new regime from November 17, 2021.

Baijal was the Delhi LG when the Arvind Kejriwal government prepared the new excise policy, which was implemented on November 17, 2021. No immediate reaction was available from Baijal.

The Deputy Chief Minister said the file on the 2021-22 excise policy went to the LG twice before getting implemented. "In the first instance, the then LG Anil Baijal sent back the file with certain suggestions and changes, which was then incorporated by the Delhi Government. The file, after making the necessary changes as suggested by the LG, was sent for a second time in November first week. The new policy was to be implemented from November 17 and the LG returned the file on November 15, just 48 hours before the launch, asking us to make major changes to it," Sisodia said.

"Under the new excise policy, 849 shops were to be opened across Delhi, including in unauthorised areas. The LG did not object to the proposal and approved it," said Sisodia adding that just before 48 hours before the launch of the policy, the LG directed that the State Government need to get permission from the Delhi Development Authority (DDA) and the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for permitting liquor shops in unauthorised colonies. Sisodia said the suggestion to consult the DDA for opening liquor vends in unauthorised colonies was not mentioned by the LG in his previous remarks on the actual excise policy of 2021-22. It was only when the file pertaining to opening liquor shops after completion of the tender and allotment of licenses to vendors went to the LG that he raised this new objection at the last moment. "As a result of this change of stand by the LG, as close to 300-350 shops that were to open in unauthorised colonies, could not be opened, leading to a loss of revenue of thousands of crores to the government. On the other hand, the shops that opened witnessed a huge income," the Deputy Chief Minister said. "As a result, the few companies who managed to open liquor shops in Delhi earned huge profits, while others suffered. The primary aim of the new excise policy was to put an end to the inequitable distribution of liquor shops, which could never be achieved because of the decision of the LG," Sisodia said, alleging L-G's "sudden change in stance" could have been intentional.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE HINDU MONDAY, AUGUST 8, 2022 ---------DATED-----------------

DDA eases EWS norms to hasten disposal of unsold inventory

Its liabilities have exceeded '₹10,000 cr.' due to poor response from homebuyers

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

With relaxation in norms for allotment of flats under the Economically Weaker Section (EWS) scheme, the Delhi Development Authority is looking to hasten the disposal of its unsold housing inventory in the Janta category that has resulted in huge cash deficit over the years.

In a written response to a question from Aam Aadmi Party member Narain Dass Gupta, Union Minister of State for Housing and Urban Affairs Kaushal Kishore informed the Rajya Sabha that as of March 31, the DDA had a cash deficit of ₹9,615 crore.

The reply further highlighted the fact that the deficit was mainly due to unsold housing inventory worth "₹18,000 crore approximately", and that it had started accumulating from the financial year 2016-17.

The factors responsible for the housing inventory remaining unsold included remote location of the flats in areas such as Narela, their small size, lack of metro rail connectivity and high cost.

No takers

According to documents accessed by *The Hindu*, housing schemes launched by the DDA since 2014 have received a poor response from homebuyers, and a majority of the unsold flats are in the Narela area.

Low-income group (LIG) flats offered by the DDA in Narela in Delhi. ▪FILE PHOTO: SUSHIL KUMAR VERMA

For instance, of the 17,922 flats offered in a housing scheme launched in 2019, as many as 15,902 flats remained unsold.

The relaxation in EWS house allotment scheme mainly involves doing away with the condition that the applicant's annual individual income should be less than ₹3 lakh. Instead, the EWS flats will now be allotted on the basis of the family income being less than ₹10 lakh per annum.

According to DDA sources, the recent relaxation for EWS applicants is "a minor boost" to help dispose of the unsold housing inventory.

"In the case of Narela, the larger problems are that of connectivity, especially because the metro rail is something that will come up in the future. This relaxation in allotment of EWS houses will not translate into immediate disposal of the flats, and the DDA will have to do something about it since the cash deficit that arose out of the failure of the housing schemes will serve as a roadblock going ahead," said the source.

In December last year, the DDA launched a special housing scheme with 18,335 flats for sale in areas such Jasola, Dwarka, Rohini, Vasant Kunj and Narela - which included 5,702 EWS/Janta flats and 11,452 flats in the Lower Income Group (LIG) category.

However, the response to the final draw, which was held in mid-April, remained poor with the DDA stating that only 9,790 flats were put up for sale in the final draw and only "5,227 flats were allotted to successful applicants".

Of the total number of EWS flats, a majority of them (5,033) were located in Narela's Sector A-1 to A-4, while a big chunk of the LIG flats (8,295) were located in Narela's Sector G-2, G-7 and G-8.

The results of the final draw witnessed few takers with only 687 applicants for LIG flats in Sector G-7 and 2,234 applicants in Sector A-1 to A-4 against the offer of 6,546 and 5,033 flats respectively, which has resulted in another poor response to the urban's body's scheme.

Due to 'mismanagement'

In early July, Lieutenant-Governor V. K. Saxena – who is also chairman of the DDA – raised the issue of the urban body's financial liabilities while stating that it had exceeded "₹10,000 crore" due to "mismanagement".

However, senior DDA officials have denied that there was any mismanagement while adding that liabilities have arisen due to the poor response from homebuyers to the urban body's schemes, leaving it with an unsold housing inventory of close to 15,000 flats.

"We are not worried about the Higher Income Group (HIG) and Middle-Income Group (MIG) flats that are located in Vasant Kunj and Dwarka, these houses will find takers and the inventory is small in number. However, the EWS and LIG flats take up most of the inventory and have to be effectively disposed of," said another source.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
MONDAY, 8 AUGUST, 2022 | NEW DELHI
NAME OF NEWSPAPERS----

LAND MEASURING AT LEAST 5,532 HECTARES IS AVAILABLE IN THE O-ZONE

Around 9,000-hectare land available in Yamuna floodplains for plantation, says Delhi forest dept

NEW DELHI: Land measuring around 9,000 hectares is available in the Yamuna floodplains, which could be used for raising plantation suitable to the river ecology and compensatory afforestation for projects of national importance, the Delhi Development Authority (DDA) has been informed by the city forest department.

The DDA has repeatedly raised the issue of "shortage" of land for greening activities in the national capital.

The forest department said it has conducted a detailed analysis of the land available for plantation in the Yamuna floodplains, considering the Centre's project to rejuvenate 13 major rivers, including the Yamuna, through forestry intervention.

The Union Environment Ministry had, in March, released the detailed project reports (DPRs) for the rejuvenation of the 13 rivers.

The DPRs focus on protection, afforestation, catchment treatment, ecological restoration, moisture conservation, livelihood improvement, income generation and eco-tourism by developing riverfronts and eco-parks.

According to the Centre, the activities proposed in the DPRs will help increase the green cover, reduce soil erosion, recharge the water table and aid carbon dioxide sequestration in addition to benefits in the form of non timber forest produce.

"As per the directions of the chief secretary, a detailed analysis of the land available for plantations in the Yamuna floodplains has been done, taking into consideration the prescription of the DPR for forestry intervention for the rejuvenation of the Yamuna and O-zone," read a forest department communication to the DDA.

Land measuring at least 5,532 hectares is available in the O-zone. Overall, the available area in the Yamuna floodplains is around 9,000 hectares, it said.

The department asked the DDA to provide inputs on the analysis, considering the "acute need for land for compensatory afforestation and plantation, and transplantation, which often hinders the progress of important projects of national importance".

It said the 9,000 hectares of land in the river floodplains is in addition to 2,480 hectares of land, which has been encroached upon or developed since 2009.

According to forest department officials, Delhi's green cover can be increased from 23 per cent at present to 25 per cent by 2025 if suitable plantation is raised in the river floodplains.

Raising the issue of land scarcity in Delhi, the DDA had earlier asked the forest department to revise the compensatory plantation scheme guidelines and bring down the number of saplings to be planted for every tree felled from 10 to two. MPOST

BJP-ruled DDA going to demolish 200 jhuggis on August 18, says AAP

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) on Sunday said that the BJP-ruled DDA has sent demolition notices to the slums of Kasturba Nagar area without stating any reason.

AAP MCD co in-charge Deepak Singla said, "BJP ruled DDA is going to demolish 200 jhuggis on August 18. Instead of protecting the people, BJP MLA Omprakash Sharma wrote to the DDA giving support to the demolition. Residents living in the slums for about 25-30 years, can't understand why BJP wants to make them homeless. AAP demands rehabilitation for all the victims before demolition."

"The BJP has decided to go on a rampage against the poor in Vishwas Nagar constituency's Kasturba Nagar area. The BJP-controlled DDA and the BJP MLA are conspiring to demolish a slum colony there. The DDA has sent a notice to the residents saying they'll demolish their houses on August 18," he said.

He added, "There are some 150-200 jhuggis in the colony that are being demolished. These jhuggis are as old as 1963, even the newest jhuggis are 25 years old. Yet, the BJP's DDA has issued demolition notices to them, without discussing it even once with residents. If this wasn't enough, BJP MLA Omprakash Sharma has very suspiciously written to the DDA seeking details and names of those people whose homes will be demolished. He has sought the details under the garb of ensuring DDA doesn't face any difficulty in clearing the slums but it seems fishy. Instead of protecting the residents, the MLA is getting their homes demolished." MPOST

पंजाब केसरी 8 अगस्त, 2022 ▶ सोमवार

'डीडीए ने झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस भेजा'

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी (आप) एमसीडी सह-प्रभारी दीपक सिंगला ने कहा कि भाजपा शासित डीडीए ने कस्तूरबा नगर क्षेत्र की झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस भेजा है। डीडीए ने 18 अगस्त को यहां 200 झुग्गियां तोड़ने की जानकारी दी है। यहां पिछले 25-30 सालों से लोग रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि यदि झुग्गियां हटानी है तो पहले लोगों को रहने के लिए अन्य स्थान दिया जाए। भाजपा ने नोटिस जारी किया है, जिसमें झुग्गियों को तोड़ने की बात कही है।

amarujala
नई दिल्ली | सोमवार, 8 अगस्त 2022

आप ने की झुग्गियां को तोड़ने के नोटिस की निंदा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने डीडीए की कस्तूरबा नगर क्षेत्र की झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस भेजने की कार्रवाई की निंदा की है। आप नेता दीपक सिंगला ने कहा कि डीडीए ने 200 झुग्गियां तोड़ने की जानकारी दी है। यहां पिछले 25-30 सालों से लोग रह रहे हैं और अब उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने झुग्गियों को बचाने के बजाय उन्हें हटाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि झुग्गियां हटाने से पहले लोगों को रहने के लिए अन्य स्थान की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली। सोमवार • 8 अगस्त • 2022 राष्ट्रीय सहारा

पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

लोकमंच

बृज विहार अपार्टमेंट, पीतमपुरा में पुष्पांजलि एनक्लेव के पास है। इस सोसाइटी के साथ एक डीडीए का पार्क है। डीडीए ने पार्क अच्छा बनाया है। इस बृज विहार पार्क में शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आवारा लड़के और लड़कियां यहां घूमते हैं, शोर मचाते हैं व अश्लील हरकतें करते हैं। बृज विहार के निवासियों को इससे परेशानी होती है। हमारा दिल्ली पुलिस के संबंधित उच्चाधिकारी से अनुरोध है कि इस पार्क व आसपास के इलाकों पुलिस गश्त बढ़ाकर यहां के निवासियों को राहत प्रदान करे।

बृज विहार के दुखी निवासी।

मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर ऑटो खड़े होने से लगता जाम

मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर रेड लाइट पर ऑटो वालों की मनमानियों से आए दिन जाम लग जाता है। यहां आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते ऑटो चालक रेड लाइट के इर्द गिर्द की सड़क घेर लेते हैं और ग्रीन सिग्नल होने पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है तथा जाम लग जाता है। हालांकि ऑटो वालों के लिए एक अलग लेन बनी हुई है। अपनी मनमानियों के चलते लोग इसका पालन नहीं करते। खास बात यह है कि अक्सर यहां ट्रैफिक पुलिस भी होती है परंतु वह भी मूक दर्शक बनी रहती है। और तो और ऑटो वाले ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हैं, जिसके चलते जानलेवा दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी ध्यान देते हुए ऑटो वालों की मनमानियों पर रोक लगाएं।

सोमदत्त तंवर, गांव मोची बाग, नानक पुरा।

रेलवे स्टेशन के आसपास खड़ी अनिगनत कैबों से यात्री परेशान

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास सुबह के समय पहाड़ गंज, कुतुब रोड पर खड़ी कैबों की लम्बी कतारों से स्टेशन के सामने सड़क पर लम्बा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके चलते स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को पैदल चलकर जाना पड़ता है और यात्रियों को भारी भरकम लगेज उठाकर पैदल चलने में असुविधा होती है। कई बार प्लेटफार्म तक पहुंचने में देर भी होती है। स्टेशन के सामने की लाल बत्ती के पास ट्रैफिक पुलिस भी जाम से निजात दिलाने में नाकाम रहती है। ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से अनुरोध है कि यात्रियों को रही असुविधा से निजात दिलाने की कोशिश करें।

प्रवीण कालड़ा, लक्ष्मी नगर।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कापसहेड़ा में गैस पाइप लाइन नहीं

गांव कापसहेड़ा कई साल पुराना गांव है, इस गांव में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गैस पाइपलाइन का काम काफी साल पहले शुरू किया था। वर्ष 2018 में घर घर आ कर साईं कुंज व अशियाना अपार्टमेंट्स में फॉर्म भी भरवाए गए थे। साथ में निर्धारित राशि के चैक भी लिए गए थे, लेकिन आज तक मटके वाली गली में पाइप लाइन नहीं आई। किसी को नहीं पता घरों में गैस कनैक्शन कब मिल जाएंगे। मेरा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि इस काम को और लम्बित न करें और जल्द से जल्द पूरा करवा कर जनता को राहत प्रदान करें।

नरेंद्र जैसवाल, कापसहेड़ा।

मच्छर मारने की दवाओं का नहीं हो रहा छिड़काव

बरसात के दिनों में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों सिरस पुर खेड़ा कलां, बादली मुबारकपुर, नरेला बाकनेर, होलंबी, नजफगढ़ व नांगलोई आदि गांव में मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली नगर निगम मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करता था अथवा मच्छरों को मारने के लिए धुआं का इस्तेमाल करता था। इस तरह से दिल्ली नगर निगम का मलेरिया विभाग बुखार और अन्य विभिन्न तरह की बीमारियों के इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों में खून के टेस्ट भी होते थे। अधिकतर उप स्वास्थ्य केंद्रों में अब इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित विभाग आवश्यक रूप से इन ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में आवश्यक रूप से कार्रवाई करे।

विजय कुमार धानिया सिरस पुर।

ट्रेन में नहीं मिल रही पूरी सुविधाएं

भारतीय रेल में आजकल यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है। एसी कोच में पहले यात्रियों को बिस्तर की सुविधा दी जाती थी, लेकिन आजकल तो तकिया कंबल बैडशीट आदि कुछ नहीं दिया जाता। यात्रियों से केवल किराया लेने में लगे रेलवे को जनता की सुविधा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बेशक उन सुविधाओं के एवज में कुछ पैसा वसूल किया जाए। रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान किया जाए।

उमेश कुमार सरीन, साईं कुंज कापसहेड़ा।

डीडीए ने बिना कारण बताए कस्तूरबा नगर क्षेत्र की झुग्गियों को तोड़ने का भेजा नोटिस

नई दिल्ली (एसएनबी)। आप एमसीडी सह-प्रभारी दीपक सिंगला ने कहा कि भाजपा शासित डीडीए ने कस्तूरबा नगर क्षेत्र की झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस भेजा है। डीडीए ने 18 अगस्त को सभी 200 झुग्गियां तोड़ने की जानकारी दी है। वहां पिछले 25-30 सालों से लोग रह रहे हैं। उन्हें बेघर किया जा रहा है। क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने डीडीए को पत्र लिखा झुग्गियों को बचाने की बात करने की बजाय उन्हें खाली करवाने की बात कही, जिससे डीडीए की कार्रवाई में कोई बाधा न आए। यह अन्याय है। यदि झुग्गियां हटानी है तो पहले लोगों को रहने के लिए अन्य स्थान दिया जाए।

सिंगला ने रविवार को एक बयान में कहा कि मैं, विश्वास नगर विधानसभा से संबंध रखता हूं। यहां, कस्तूरबा नगर नाम की एक कॉलोनी है जिसमें बसी 150-200 झुग्गियों को बिना किसी कारण भाजपा शासित डीडीए ध्वस्त करने की साजिश कर रही है। भाजपा ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 18 अगस्त को झुग्गियों को तोड़ने की बात कही है। 1963 से लोग उन झुग्गियों में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि यह लोग लगभग 25-30 सालों से वहां रह रहे हैं। आज अचानक उन्हें बेघर करने की कोशिश हो रही है।

'DDA has sent demolition notices to Kasturba Nagar shanties sans any reason'

Pioneer 8/8/2022

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Aam Aadmi Party (AAP) on Sunday alleged the BJP-ruled Delhi Development Authority (DDA) has sent demolition notices to the slums of Kasturba Nagar area without stating any reason.

The AAP leader, Deepak Singla said BJP-ruled DDA is going to demolish 200 jhuggis on August 18.

"Instead of protecting the people, BJP MLA Omprakash Sharma wrote to the DDA giving support to the demolition. Residents living in the slums for about 25-30 years, can't understand why BJP wants to make them homeless. AAP demands rehabilitation for all the victims before demolition," said Singla.

"The BJP has decided to go on a rampage against the poor in Vishwas Nagar constituency's Kasturba Nagar area.

The BJP controlled DDA and the BJP MLA are conspiring to demolish a slum colony there. The DDA has sent a notice to the residents saying they'll demolish their houses on August 8," said Singla.